23/4/18

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, 'कर-भवन', अजमेर

क्रमांकः एफ-7(507)परिपत्र/18/ दिनांकः

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
जयपुर

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
वृत-राजस्थान

विषयः- श्रम न्यायालय में लम्बित श्रमिक संबंधी मामलों में श्रम एंव नियोजन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति के नामर्स निर्धारण करने के संबंध में प्रसारित परिपत्र के संबंध में।

प्रसंगः- संयुक्त विधि परामर्शी वित (विधि प्रकोष्ठ) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(विविध) वित./विप्र/2016 पार्ट I दिनांक 28.03.18 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि वित्त विभाग के पत्र दिनांक 28.03.2018 के साथ प्राप्त श्रम विभाग के परिपत्र दिनांक 20.03.18 के द्वारा श्रम न्यायालय में लम्बित श्रमिक संबंधी मामलों में श्रम एंव नियोजन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति के नामर्स निर्धारण किये है।

अतः श्रम विभाग के परिपत्र दिनांक 20.03.2018 की प्रति ***संलग्न*** कर भिजवायी जा रही है। अतः उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

Sd/

संयुक्त विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

Pr.99-I
3/4
25/4/18

क्रमांकः एफ-7(507)परिपत्र/18/ 1437 दिनांकः 23-04-18

प्रतिलिपिः-

1. संयुक्त विधि परामर्शी को आपके पत्र क्रमांक प.14(विविध) वित./विप्र/2016 पार्ट-I दिनांक 28.03.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर) मुख्यालय, अजमेर को उपरोक्त परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट पर igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।

संयुक्त विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-507-1

Government of Rajasthan

Office of the Secretary, Skills, Employment & Entrepreneurship, Labour, Factories & Boiler and ESI

www.livelihoods.rajasthan.gov.in https://ldms.rajasthan.gov.in

File No. F.14 (13) (12)Shram/law/2017 Jaipur, Dated : 20.3.2018

1253

To,

All Addl. Chief Secretaries/
Principal Secretaries/ Secretaries to Government of Rajasthan,
Secretariat, Jaipur (Raj.)

Sr JT LR
JSF. (Tax)
JSF (Rev)
JSF (Excise)

CIRCULAR

In the course of hearing of S.B. Civil writ petition No. 253/2017, Additional Chief Executive Officer & Anr. v. Madan Lal Sharma, vide order dated 29.11.2017 the Hon'ble High Court of Rajasthan observed that, "*the various Labour Courts are awarding compensation in lieu of reinstatement, however, the amount of compensation being awarded is markedly different by the various Labour Courts*".

Since it leads to further litigation in cases related to workmen under the Industrial Disputes Act, 1947. Hon'ble High Court observed that uniformity in granting compensation should be maintained. Accordingly, Hon'ble High Court directed the State Government to come up with a proposal for uniform amount of compensation, which is required to be paid to a workman in lieu of reinstatement, where reinstatement is not possible.

The matter was discussed in the meeting chaired by Chief Secretary. It was agreed upon for uniformity in granting compensation, in the cases where reinstatement is not possible.

Accordingly, Finance Department approved the following norms of compensation:

S.No.	Age of the workmen at the time of termination of services	Lump-sum compensation amount to be granted
1	18 yrs. to 24 yrs.	Rs. 2.00 Lacs
2	25 yrs. to 31 yrs.	Rs. 1.50 Lacs
3	32 yrs. to 38 yrs.	Rs. 1.00 Lac
4	39 yrs. and above	Rs. 50,000/-

All Administrative Departments are hereby directed to take note of the above mentioned norms while pleading cases of workmen under the Industrial Disputes Act, 1947, where reinstatement is not possible, in Labour Courts/Industrial Tribunals.

This bears the approval of the Finance Department vide ID No. 101706539 dated 28.12.2017.

21 MAR 2017

20/3/2018
(T. Ravikanth)
Secretary

AH HOD
AH Law officer

Telefax: 0141-2227061 email: secretary.skills.labour@rajasthan.gov.in Room No. 5225, Secretariat, Jaipur